योग करें या ना करें पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।

– अज्ञात

फिर वही सियासी खेल

कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार गठन के बारे में बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया जबकि शिवसेना को समर्थन पत्र हासिल करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। एनसीपी को तो उन्होंने 12 घंटे में ही निपटा दिया।

नमन जोशी

सरकार बनाने की 19 दिन की उठापटक के बाद महाराष्ट्र में मंगलवार को भले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो, लेकिन वहां सरकार के गठन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। सचाई यह है कि राज्यपाल ने अगर पर्याप्त धैर्य दिखाया होता तो राष्ट्रपति शासन की नौबत ही नहीं आती। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने पर सहमति तकरीबन बन ही चुकी थी। लेकिन गवर्नर ने थोड़ा और इंतजार करना बेहतर नहीं समझा। हमारी संघीय प्रणाली में सबसे आदर्श स्थिति यही मानी जाती है कि राज्यपाल द्वारा सरकार के गठन की हर संभव कोशिश की जाए। लगता है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विभिन्न दलों के बीच लगातार असमंजस की स्थिति को सियासी अस्थिरता का संकेत मान लिया।

संभव है, वे भविष्य के प्रति आश्वस्त न हो पाए हों, पर उन्होंने जिस तरह से बहुमत साबित करने के लिए दोनों पक्षों में भेदभाव किया उससे पिछले कुछ समय से लगातार लग रहे इस आरोप को मजबूती मिलती है कि राज्यपाल अब सारे फैसले केंद्र सरकार को खुश रखने के लिए ही करने लगे हैं। कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार गठन के बारे में बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया जबकि शिवसेना को समर्थन पत्र हासिल करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। एनसीपी को तो उन्होंने 12 घंटे में ही निपटा दिया। यही वजह है कि शिवसेना ने उनके रुख को जल्दबाजी भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और अदालत से मांग की कि वह शिवसेना को सरकार के गठन के लिए उचित समय दिए जाने का निर्देश जारी करे।

इस तरह राज्यपाल के निर्णयों को अदालत में चुनौती दिया जाना हमारी व्यवस्था के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। असल में केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने ऐसे विश्वासपात्र जनों को ही राजभवन भेजते हैं, जो निर्णायक समय में उनके काम आ सकें। इसमें हीलाहवाली करने वाले राज्यपालों को वापस बुला लेने या छोटे अ–महत्वपूर्ण राज्यों में भेज देने की परंपरा मजबूत हो चली है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही राज्यपाल जब–तब बिल्कुल मनमाने फैसले पर उतारू हो जाते हैं तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन उस पर जब तक फैसला आता है, तब तक केंद्र की मनमाफिक सरकार के प्रतिनिधि पर्याप्त सत्ता सुख भोग चुके होते हैं। नतीजा यह कि जनादेश कई बार बेमानी होकर रह जाता है।

बहरहाल, महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिश जारी है। बुधवार को कांग्रेस और एनसीपी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए 5–5 नेताओं की एक कमेटी बनाई। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार चलाने के नए सूत्र तलाश रही हैं। सरकार के गठन की ज्यों ही गुंजाइश पैदा हो, राज्यपाल को तत्परता दिखाते हुए उसे बनवा देना चाहिए, तभी वे अपने ऊपर लग रहे आरोपों से मुक्त हो सकेंगे। इसमें देर होने से विधायकों की खरीद–फरोख्त के अलावा कर्नाटक की तर्ज पर उनसे इस्तीफे दिलाकर मनमाफिक सरकार बनवा लेने की आशंका भी बढ़ेगी।

वास्तविक खुशी

योगाचार्य गोस्वामी

धर्म-दर्शन

अभिभावक होने के नाते आपकी ये चिंता गलत नहीं है, परंतु अपने बेटे के पुनर्विवाह को ही अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लेंगे तो यह सही नहीं है। आप बस एक सीमा तक ही उन पर दबाव डाल सकते हैं, संतान पर किसी भी प्रकार से भावनात्मक रूप से दबाव डालना सही नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे आपका उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो।

आप उनके माता–पिता है और आपका कर्तव्य है उनका सही मार्गदर्शन करना। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि विवाह ही खुशियों की सीढ़ी है? हो सकता आपकी संतान का दूसरा विवाह सफल हो... वह एक वयस्क हैं और उन्हें क्या करना है इसका निर्णय आप उन्हें ही लेने दें तो बेहतर होगा। हो सकता है उनके पास भी कुछ ऐसे कारण हों, जिसकी वजह से वे पुनः विवाह ना करना चाहते हों।

संपादकीय

कोचिंग का नया जलवा

भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर हमें एक चीनी मोबाइल कंपनी की जगह एक भारतीय एजूकेशन टेक्नॉलजी कंपनी का नाम दिख रहा है। इस बदलाव से सिर्फ इस कंपनी का कारोबार अच्छा जाने का संकेत नहीं मिलता। यह जानकारी भी मिलती है कि पहली बार भारत में शिक्षा के दायरे में काम करने वाली एक कंपनी बड़ी पूंजी के टॉप क्लास खेल में शामिल हो रही है। 5.4 अरब डॉलर (करीब 37,000 करोड़ रुपये) की टोटल नेटवर्थ और दुनिया की मोस्ट वैल्यूड एड–टेक कंपनी का खिताब हासिल कर लेने के बाद दुनिया की नजर में चढ़ने का उसका हक बनता है। कंपनी का मूल व्यवसाय कक्षा–1 से लेकर आईएएस परीक्षाओं की तैयारी तक अलग–अलग लेवल की पढ़ाई में स्टूडेंट्स की मदद करना है।

देश में फलती–फूलती कोचिंग इंडस्ट्री के सबूत हमें अलग–अलग रूपों में मिलते रहे हैं, फिर चाहे वह मेनस्ट्रीम बॉलिवुड फिल्म सुपर थर्टी की रिलीज हो या कोटा में खुदकुशी करते स्टूडेंट्स की खबरें। गुणवत्ता को बढ़ावा देने के नाम पर अभी तीसेक साल पहले हमने देश में शिक्षा के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का जो दोहरा ढांचा तैयार किया था, हैरानी की बात है कि देखते–देखते उसके समानांतर ट्यूशन और कोचिंग की इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कि इस पूरे ढांचे की उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं बची। ऐसे ही एक प्रयोग को कोई कंपनी बड़े पैमाने की कमाई का जरिया बनाती है तो इसके लिए उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। लेकिन ट्यूशन और कोचिंग इंडस्ट्री की कामयाबी से हमारे शिक्षा ढांचे की जिस बुनियादी नाकामी का अंदाजा मिलता है, उससे निपटने के उपाय तो हमें खोजने ही होंगे।

प्रीति पटेल की गिनती भारत से बाहर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलने वाले राजनेताओं में होती रही है। आलोक शर्मा भारत में ही जन्मे हैं। जबकि ऋषि सुनक इनफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं।

उनके मंत्री अपने लोग

मनीषा गुरूरानी

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी जो मंत्रिमंडलीय टीम घोषित की है, उसमें तीन भारतीयों का होना अभूतपूर्व है। इससे भी बड़ी बात यह कि इन तीनों नेताओं– प्रीति पटेल, आलोक शर्मा और ऋषि सुनक को बेहद अहम भूमिकाएं सौंपी गई हैं। प्रीति पटेल बतौर गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। आलोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री होंगे और ऋषि सुनक ट्रेजरी के चीफ सेक्रेट्री होंगे, जो ब्रिटेन में वित्त राज्य मंत्री जैसा पद है। वित्त मंत्री का पद पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद के जिम्मे है। जिन तीनों मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, उनका भारत से केवल भावनात्मक रिश्ता नहीं है। ये सीधे तौर पर भारत से जुड़े रहे हैं और अपने इस जुड़ाव को रेखांकित भी करते रहे हैं।

प्रीति पटेल की गिनती भारत से बाहर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलने वाले राजनेताओं में होती रही है। आलोक शर्मा भारत में ही जन्मे हैं। जबकि ऋषि सुनक इनफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ब्रिटेन की सरकार में अहम भूमिका में आए ये भारतीय दुनियाभर में प्रवासी भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बनकर उभरे हैं। बेशक ऐसा पहली बार हुआ है

कि किसी देश की सरकार में एक साथ तीन भारतीयों को इतनी बड़ी भूमिकाएं मिल गई हों लेकिन विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय की बढ़ती राजनीतिक हैसियत कुछ समय पहले से जाहिर हो रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आम चुनावों में भारतीय समुदाय को प्रभावित करना सभी पार्टियों की प्राथमिकता में होता है।

कनाडा में भारतीय मूल के जगमीत सिंह मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में संसद के निचले सदन में जाकर रेकॉर्ड बना चुके हैं। 2015 में वहां भारतीय सांसदों की संख्या 19 तक पहुंच गई थी। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैसे–जैसे दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, वैसे–वैसे विभिन्न देशों की राजनीति में भारतीयों का मुकाम भी ऊंचा हो रहा है।

वहां वे जैसे–तैसे गुजारा करने वाले समुदाय के रूप में नहीं, आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में पहचाने जा रहे हैं। बहरहाल, बोरिस जॉनसन की टीम के मौजूदा स्वरूप के पीछे उनकी अलग तरह की चुनौतियों और इनसे जुड़ी जरूरतों का हाथ है। यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ने के बाद ब्रिटेन को सबसे ज्यादा उम्मीद पुराने ब्रिटिश साम्राज्य यानी राष्ट्रमंडल देशों से ही है। इस जुड़ाव को नया रूप देकर ब्रिटेन उस नुकसान की भरपाई करना चाहता है, जो ईयू से अलग होने के बाद उसके हिस्से आएगा। इस कठिन समय में ब्रिटेन को नेतृत्व देने और उसे इस भंवर से सुरक्षित निकाल ले जाने की जो बड़ी जिम्मेदारी भारतीय मूल के नेताओं के कंधों पर आई है, उसे अच्छे से निभाकर वे इस देश में भारतीयों की प्रतिष्ठा और बढ़ा सकते हैं।

सूडोकु नवताल- 5157

सरल

5	9			3			8	7
8	7		1		5			
		2			9			4
	6				2		3	5
3	8		4	1	7		2	9
2	4		6				1	
7			3			8		
			5		8		7	3
9	3			2			6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5156 का हल

7	4	8	3	9	2	1	5	6
2	6	9	5	7	1	8	4	3
3	1	5	4	8	6	7	2	9
5	7	4	8	6	9	3	1	2
8	9	1	2	3	4	6	7	5
6	3	2	1	5	7	4	9	8
4	8	7	6	2	5	9	3	1
9	2	6	7	1	3	5	8	4
1	5	3	9	4	8	2	6	7

अपना ब्लॉग

सत्ताशीर्ष को सजा दिलाने वाला लोकतंत्र

बालमुकुंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर न्यू यॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट की जज सेलियाना स्कारपुला ने बीस लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह फैसला पिछले गुरुवार को सुनाया गया। अमेरिका में फेडरल न्यायपालिका के अलावा राज्यों की अपनी अलग न्यायपालिकाएं भी हैं जो हालांकि फेडरल सुप्रीम कोर्ट के नीचे होती हैं, लेकिन फेडरल कोर्ट शायद ही कभी इनके फैसलों में हस्तक्षेप करता है। स्टेट कोर्ट्स राज्य के अपने कानून से संबंधित मामले देखती हैं इसलिए आम तौर पर इनके सामने वैसे ही मामले आते हैं जो राज्य की कानून–व्यवस्था के उल्लंघन से जुड़े होते हैं और अपनी प्रकृति में आपराधिक होते हैं। न्यू यॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप पर पैसों के दुरुपयोग का मामला चल रहा था। उनके खिलाफ यह मुकदमा वहां के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था। मामला यह था कि ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने चौरिटेबल संगठन ट्रंप फाउंडेशन के पैसों का इस्तेमाल किया था और इसमें उनके तीन बड़े बेटे भी शामिल थे।